

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 88

दिनांक 24.02.2015/05 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

मॉडल पुलिस स्टेशन

†88. श्री तारिक अनवर:

श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:

श्री राम चरित्र निषाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में स्मार्ट पुलिस स्टेशन/मॉडल पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इन स्टेशनों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता सहित सभी सहायता दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इसमें कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के माध्यम से निजी क्षेत्र को शामिल करने पर विचार कर रही है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या सरकार ने राज्यों को विशिष्ट स्थानों और अन्य संघटकों सहित अपने प्रस्ताव सौंपने का निदेश दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (च): दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को आयोजित पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 49वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने एस.एम.ए.आर.टी. पुलिस की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें 'एस' का तात्पर्य संवेदनशील और सख्त, 'एम' का तात्पर्य गतिशीलता के साथ आधुनिक, 'ए' का तात्पर्य सतर्क और जवाबदेह, 'आर' का तात्पर्य विश्वसनीय और अनुक्रियाशील तथा 'टी' का तात्पर्य प्रशिक्षित और तकनीक की समझ से है। सरकार ने प्रत्येक राज्य में एक मॉडल स्मार्ट पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने ऐसे पुलिस स्टेशन बनाने के लिए एक योजना तैयार की है।
